[2018] 1 एस. सी. आर 86

मैसर्स आईनॉक्स विंड लिमिटेड

बनाम

मैसर्स थरमोकैबल्स लिमिटेड

(2018 की सिविल अपील संख्या 19)

05 जनवरी, 2018

[एस. ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जे. जे.]

मध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11 (6)- अपीलकर्ता द्वारा केबलों की आपूर्ति के लिये प्रत्यर्थी को खरीद आदेश जारी किये गये- प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को केबलों की आपूर्ति कर दी गई- केबलों को बिछाते समय, यह पाया गया कि केबलों के बाह्य खोल में दरार आई हुई थी- अपीलकर्ता द्वारा बदलने की मांग की गई- प्रत्यर्थी कंपनी ने केबलों को नहीं बदला- अपीलकर्ता ने मानक नियमों और शर्तों के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के नाम का प्रस्ताव करने वाली सूचना जारी की -किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा11 (6) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि मानक नियम और शर्तों में मध्यस्थता खंड का कोई विशेष संदर्भ नहीं था, इसलिए मध्यस्थता खंड को खरीद आदेश में शामिल नहीं कहा जा सकता है- अभिनिर्धारित किया : खरीद आदेश के अनुसार, आपूर्ति शर्तों और आदेश में उल्लिखित

और उससे जुड़े मानक नियम और शर्तें के अनुसार होनी थी- अन्य शर्तों के अलावा, मानक नियम और शर्तों में विवाद समाधान से संबंधित एक खंड शामिल था- अभिलेख पर सामग्री इंगित करती है कि उत्तरदाता ने डिलीवरी अवधि को छोड़कर खरीद में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है- आदेश- खरीद आदेश एक एकल अनुबंध और मानक प्रपत्र के लिए सामान्य संदर्भ है भले ही यह किसी व्यापार संघ या किसी पेशेवर निकाय द्वारा मध्यस्थता खंड का समावेश करने के लिये पर्याप्त न हो, -इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया-पक्षकारों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. यद्यपि पूर्ववर्ती अनुबंध का सामान्य संदर्भ परवर्ती अनुबंध में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एक मानक रूप के लिए एक सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। एम. आर. में इंजीनियरों के मामले में, इस न्यायालय ने व्यापार संघों और पेशेवर संस्थानों के अनुबंध के मानक रूप के अपवादों को प्रतिबंधित कर दिया। एम. आर. इंजीनियर्स के मामले में निर्णय के बाद कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि एक मध्यस्थता खंड का समावेश करने के लिये सहमति से मानक प्रपत्र का एक सामान्य संदर्भ पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, सामान्य मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए एक पक्ष के अनुबंध के मानक रूप का संदर्भ पर्याप्त होगा। मध्यस्थता **24** वें संस्करण **(2015)** पर रसेल के परिच्छेद का अवलोकन निगमन से संबंधित कानून की स्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा जब एम. आर. इंजीनियर्स के मामले में इस न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए पिछले संस्करण के संयोजन में पढ़ा गया था। यह न्यायालय

एम. आर. इंजीनियर के मामले में एक संशोधन के साथ फैसले से सहमत है कि मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए व्यापार संघों और पेशेवर निकायों के साथ एक पक्ष के अनुबंध के मानक रूप का सामान्य संदर्भ पर्याप्त होगा। **[पैरा 19] [100-एफ एच; 101-ए]**

2. वर्तमान मामले में, खरीद आदेश अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आपूर्ति उसमें उल्लिखित शर्तों और संलग्न मानक नियमों और शर्तों के अनुसार होगी। उत्तरदाता ने उसके द्वारा पत्र के माध्यम से डिलीवरी अवधि को छोड़कर खरीद आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि की। माल की डिलीवरी के बाद विवाद पैदा हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों या प्रस्तुतियों से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि खरीद आदेश से जुड़ा मानक प्रपत्र किसी व्यापार संघ या किसी पेशेवर निकाय का है। हालाँकि, प्रत्यर्थी खरीद आदेश से जुड़े मानक नियमों और शर्तों से अवगत था। क्रय आदेश एक एकल अनुबंध है और मानक प्रपत्र के लिए सामान्य संदर्भ भले ही यह किसी व्यापार संघ या किसी पेशेवर निकाय द्वारा न हो, मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। **[पैरा 20] [101 बी-डी]**

एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696 [2009] 10 एस. सी. आर. 373- पर भरोसा किया गया।

सी ट्रेड मैरीटाईम कोर्पोरेशन बनामबनाम हैलेंसिक म्युचुअल वार रिस्क्स एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, द एथेना [2006] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2530 (कॉम); हबास सिनाई वे टिब्बी गज़लार इस्तिसल एंडस्ट्री ए. एस. बनाम समताल एस. ए. एल.

[2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी 29 (कॉम); ऑघटन बनाम एम. एफ. केंट सर्विसेज [1991] 31 कोन एल. आर. 60- संदर्भित किया गया।

मध्यस्थता 24 वें संस्करण (2015) पर रसेल- संदर्भित किया गया।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2009] 10 एससीआर 373	पभरोसा किया गया	पैरा 5
[2006] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2530(कॉम)	संदर्भित किया गया	पैरा 12
[2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 29 (कॉम)	संदर्भित किया गया	पैरा 13
[1991] 31 कोन एल. आर. 60	संदर्भित किया गया	पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2018 की सिविल अपील सं. 19

2015 के सी.एम.ए.ए. संख्या 2 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के 20.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनूप जैन, पुलकित श्रीवास्तव, सुश्री दिशा वैश - अपीलार्थी के लिए।

के. राजेंद्रन, ए. टी. एम. संपत, एस. के. बंदोपाध्याय, सुरंगमा बनर्जी, राहुल नागपाल - उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा निष्पादित किया गया-

एल**.** नागेश्वर राव**,** जे**.**

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्षेत्राधिकार के फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

3. अपीलार्थी पवन टरबाइन जनरेटरों (डब्ल्यूटीजी) का निर्माता है। प्रतिवादी पवन ऊर्जा केबलों और अन्य प्रकार के केबलों के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपने डब्ल्यू. टी. जी. के लिए केबलों की आपूर्ति के लिए उत्तरदाता को दो खरीद आदेश दिनांकित 13.12.2012 और 02.02.2013 जारी किए गए थे। क्रय आदेश के अनुसार, आपूर्ति आदेश में उल्लिखित शर्तों और उससे जुड़े मानक नियमों और शर्तों के अनुसार होनी थी। अन्य शर्तों के अलावा, मानक नियमों और शर्तों में विवाद समाधान से संबंधित एक खंड है। उक्त खंड में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा विवाद का समाधान करने का प्रावधान है। अभिलेख पर सामग्री इंगित करती है कि प्रत्यर्थी ने डिलीवरी अवधि को छोड़कर खरीद आदेश में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया जैसा कि पत्र दिनांकित 15.12.2012 से स्पष्ट है।

4. प्रत्यर्थी ने, खरीद आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को पवन ऊर्जा केबलों की आपूर्ति की। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई तारों को बिछाते समय अपीलार्थी ने पाया कि, तारों के 150 वर्ग मिमी बाहरी आवरण टूट गए थे। इसने उन्हें डब्ल्यू. टी. जी. को रोकने के लिए मजबूर किया ताकि महंगे उपकरणों को नुकसान न हो। अपीलार्थी के

अनुसार, प्रत्यर्थी-कंपनी ने तारों को नहीं बदला। इसलिए, अपीलार्थी को मानक नियमों और शर्तों के संदर्भ में एकल मध्यस्थ के नाम का प्रस्ताव करते हुए दिनांक 30.10.2014 का एक नोटिस जारी करने के लिए विवश किया गया था। किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर करके इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का रुख किया।

5. उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि अपीलार्थी ने मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व साबित नहीं किया। उच्च न्यायालय ने एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड, **(2009) 7** एस. सी. सी. **696** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि मानक नियमों और शर्तों में मध्यस्थता खंड का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, इसलिए मध्यस्थता खंड को खरीद आदेश में शामिल किया गया नहीं कहा जा सकता है।

6. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के वकील को सुना है। एम. आर. इंजीनियर्स के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर दोनों पक्षों ने भरोसा किया था। आगे बढ़ने से पहले, उक्त निर्णय के सारांश का अवलोकन करना आवश्यक होगा। उक्त मामले में विवाद को समझने के लिये कुछ तथ्य आवश्यक हैं - कि उसमें अपीलार्थी प्रत्यर्थी का उप-ठेकेदार था। अपीलार्थी को कार्य का एक हिस्सा प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा सौंपा गया था जो 'परियोजना निदेशालय भवन के निर्माण' से संबंधित था। उप अनुबंध में इसका उल्लेख किया गया था कि यह मुख्य अनुबंध पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार

निष्पादित किया जायेगा। पार्टियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसने अपीलकर्ता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिये विवश किया। केरल उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि मध्यस्थता मुख्य अनुबंध में मध्यस्थता खंड को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच अनुबन्ध में संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसका मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत आता है और मुख्य अनुबंध से मध्यस्थता खंड को उसके और प्रतिवादी के बीच उप अनुबंध में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था।

7. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 (5) के दायरे पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि दूसरे दस्तावेज़ में पाई गई मध्यस्थता खंड की सचेत स्वीकृति अनुबंध में शामिल करने के उद्देश्य से आवश्यक है। यह भी माना गया कि अनुबंधों के निर्माण के सामान्य नियम में इसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 7 (5) में उन शर्तों के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी, जिसमें उसमें निहित मध्यस्थता खंड के साथ पूरे अनुबंध के एक हिस्से के संदर्भ को एक संदर्भ के रूप में शामिल किया गया था। एक अन्य दस्तावेज़ के 'संदर्भ' को 'निगमन' से अलग करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि प्रासंगिक कारक पक्षों का इरादा या तो दस्तावेज़ को पूरी तरह से अपनाना था या उक्त दस्तावेज़ के विशिष्ट

भागों को उधार लेना था। इस संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः **(एम. आर. इंजीनियर्स का मामला, पैरा 17-19)**

"17. हम स्थिति की व्याख्या करने के लिए निगमन और केवल संदर्भ के कुछ उदाहरण देंगे (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं)। यदि कोई अनुबंध किसी दस्तावेज़ को संदर्भित करता है और यह प्रदान करता है कि उक्त दस्तावेज़ अनुबंध का एक हिस्सा होगा, या कि उक्त दस्तावेज़ के सभी नियमों और शर्तों को अनुबंध के एक हिस्से के रूप में पढ़ा या माना जाएगा, या कि अनुबंध उक्त दस्तावेज़ के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, या कि उक्त दस्तावेज़ के नियम और शर्तें अनुबंध में शामिल की जाएंगी, दस्तावेज़ के नियम और शर्तें पूरी तरह से भौतिक रूप से उठ जायेंगी और अनुबंध में शामिल हो जायेंगी, जब किसी दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को इस तरह से शामिल किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज़ की प्रत्येक अवधि (उस सीमा को छोड़कर जो अनुबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के साथ असंगत है) अनुबंध पर लागू होगी। यदि इस प्रकार शामिल किए गए दस्तावेज़ में मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान का प्रावधान है, तो अनुबंध के लिए उक्त मध्यस्थता खंड भी लागू होगा।

18. दूसरी ओर, जहाँ एक विशेष संदर्भ में एक अनुबंध में केवल एक दस्तावेज़ का संदर्भ है तो, दस्तावेज़ पूरी तरह से अनुबंध में

शामिल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुबंध यह प्रदान करता है कि आपूर्ति के विनिर्देश पहले के अनुबंध या किसी अन्य खरीद आदेश में दिए गए आदेश के अनुसार होंगे, तो उस दस्तावेज को केवल आपूर्ति किए जाने वाले माल के विनिर्देशों के निर्धारण के सीमित उद्देश्य के लिए देखना आवश्यक होगा। संदर्भित दस्तावेज़ को किसी भी मामले में अन्य उद्देश्य के लिये नहीं देखा जा सकता है, यथा मान लीजिए कीमत या कीमत का भुगतान आदि के लिये। इसी तरह, यदि एक्स और वाई के बीच एक अनुबंध यह प्रदान करता है कि वाई को भुगतान की शर्तें जैसा कि एक्स और जेड के बीच अनुबंध में है, के अनुसार होंगी तो, केवल एक्स और जेड के बीच अनुबंध से भुगतान की शर्तों को एक्स और वाई के बीच अनुबंध के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, मात्रा या डिलीवरी पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

19. धारा 7 की उप-धारा (5) केवल अनुबंधों के निर्माण के इन अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को दोहराती है। यह स्पष्ट करती है कि जहां किसी अनुबंध में किसी दस्तावेज़ का संदर्भ है, और संदर्भ से पता चलता है कि दस्तावेज़ को पूरी तरह से शामिल करने का इरादा नहीं था, तो संदर्भ दस्तावेज में मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा

नहीं बनायेगा, जब तक कि इसे लागू करने लिये मध्यस्थता खंड का कोई विशेष संदर्भ न हो।"

8. मध्यस्थता 23 वें संस्करण पर रसेल के प्रासंगिक अंश (2007) जिन पर इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा की व्याख्या के लिए भरोसा किया गया था, वे इस प्रकार हैं: (एम. आर.इंजीनीयर्स का मामला, पैरा 20-21)

"20. मध्यस्थता पर रसेल के निम्नलिखित अंश भारतीय अधिनियम की धारा 7 (5) के अनुरूप (अंग्रेजी) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 6 (2) से निपटने के दौरान स्थिति पर काफी प्रकाश डालते हैं। (पृष्ठ 52-55 23 वां संस्करण देखें),:

एक अन्य दस्तावेज़ का संदर्भ - एक अनुबंध की शर्तों को एक से अधिक दस्तावेज़ों के संदर्भ में निर्धारित करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करना कि कौन से दस्तावेज संविदात्मक दस्तावेज़ गठित करते हैं, और प्राथमिकता के किस क्रम में करते है, यदि कोई हो, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, कई वाणिज्यिक लेन-देन में एक समस्या है, विशेष रूप से शिपिंग और निर्माण से जुड़े लेन-देन में। इस मुद्दे को निर्माण के सामान्य सिद्धांत और साक्ष्य के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के माध्यम से पक्षों के इरादों का अनुमान लगाने को प्रयास को लागू करके निर्धारित करना होगा। यह निगमन के प्रश्नों को अप्रासंगिक बना सकता है,

उदाहरण के लिए यह स्पष्ट है कि विचाराधीन संविदात्मक दस्तावेज पूरी तरह से अलग हैं और एक की शर्तों को दूसरे में शामिल करने का कोई इरादा स्थापित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, निष्पादन दायित्वों को परिभाषित करने और लागू करने वाले संविदात्मक दस्तावेज़ को किसी अन्य दस्तावेज़ को शामिल करने के लिए पाया जा सकता है जिसमें एक मध्यस्थता समझौता शामिल है। अगर निष्पादन दायित्वों के बारे में कोई विवाद है, तो उस विवाद को उस अन्य दस्तावेज़ के मध्यस्थता प्रावधानों के अनुसार तय करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बहुत आम तौर पर तब होता है जब प्रधान संविदात्मक दस्तावेज़ एक मध्यस्थता समझौते वाले मानक रूप की शर्तों को संदर्भित करता है। हालांकि मानक रूप शब्दांकन उस अनुबंध के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है जिसमें पक्ष इसे शामिल करना चाहते हैं, या संदर्भ पार्टियों के बीच किसी अन्य अनुबंध के लिए हो सकता है जिनमें से कम से कम एक अलग है। इन परिस्थितियों में यह तर्क देना संभव हो सकता है कि मध्यस्थता समझौते का कथित समावेश अप्रभावी है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के मसौदा तैयार करने वालों को इस मुद्दे पर विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने यह तय करने के

लिए इसे अदालत पर छोड़ना पसंद किया कि क्या संदर्भ द्वारा एक वैध निगमन किया गया था। (पैरा 2.044)

शर्तों को निर्धारित करने वाले दस्तावेज़ में निहित मध्य्स्थता समझौते के समावेश और कुछ अन्य अनुबंध विभिन्न पक्षों में निहित एक अन्य सम्झौते के बीच अंतर करने के बावजूद, ऐसा लगता है कि न्यायिक सोच ने ऑग्टन में सर जॉन मेगॉ के रुख का समर्थन किया है, अर्थात्, निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि, मध्यस्थता अधिनियम, *1996* के *6* का पालन करने के लिए मध्यस्थता खंड का विशेष रूप से संदर्भ लिया जाना चाहिए, जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ न हों। *(*पैरा *2.047)*

मानक रूप शब्दों का संदर्भ। यदि जिस दस्तावेज़ को शामिल करने की मांग की गई है, वह नियमों और शर्तों का एक मानक रूप है, तो अदालतों द्वारा स्वीकार करने की अधिक संभावना है कि सामान्य शब्दों का समावेशन पर्याप्त होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टियों से उन मानक शब्दों से अधिक परिचित होने की उम्मीद की जा सकती है जिनमें मध्यस्थता खंड शामिल है। *(* पैरा *2.048)*

21. ऑग्टन लिमिटेड बनाम एम. एफ. केंट सर्विसेज लिमिटेड [(1991) 57 बी. एल. आर. 1] में सर जॉन मेगॉ के दृष्टिकोण का उल्लेख करने के बाद कि एक मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए विशिष्ट शब्द आवश्यक थे और कि किसी अनुबंध के उप-अनुबंध में किसी अन्य उप-अनुबंध के नियमों और शर्तों का संदर्भ मध्यस्थता खंड में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, बैरेट एंड सन (ब्रिकवर्क) लिमिटेड बनाम हेनरी बूट मैनेजमेंट लिमिटेड [1995 सी.

आई. एल. एल. 1026], ट्रिग हंसा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इक्विटास लिमिटेड [(1998) 2 लॉयड्स प्रतिनिधि 439] और ए. आई. जी. यूरोप (यू. के.) लिमिटेड बनाम एथनिकी [(2000) 2 सभी ई. आर. 566 (सी. ए.)] और सी ट्रेड मैरीटाईम कोर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हेलेनिक म्युचुअल वार रिस्क्स ऐसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड नंबर 2 [2006 ईडब्ल्यूएचसी 2530] में अनुसरण किया गया, रसेल ने निष्कर्ष निकालाः

"इसलिए वर्तमान स्थिति यह प्रतीत होती है कि यदि मध्यस्थता समझौते को एक मानक रूप से शामिल किया जाता है तो उन शर्तों का एक सामान्य संदर्भ पर्याप्त है, लेकिन कम से कम निर्माण और पुनर्बीमा अनुबंधों और लदान के बिलों के संदर्भ में एक गैर-मानक फॉर्म अनुबंध के संदर्भ के मामले में मध्यस्थता समझौते का एक विशिष्ट संदर्भ आवश्यक है।"

9. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 (5) के दायरे पर चर्चा की और उसका सार इस प्रकार निकाला: (एम. आर. इंजीनियर्स का मामला, पैरा 24)

"24. अतः अधिनियम की धारा 7 (5) का दायरा और आशय संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:

(i) किसी अन्य दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड, संदर्भ द्वारा किसी अनुबंध में निगमित हो जायेगा, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता हैः

(1) अनुबंध में दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए।

(2) अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ में स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड को अनुबंध में शामिल करने के इरादे का संकेत होना चाहिए,

(3) मध्यस्थता खंड उचित होना चाहिए, जो अनुबंध के तहत विवादों के संबंध में आवेदन करने में सक्षम है और अनुबंध की किसी भी शर्त के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

(ii) जब पक्ष किसी अन्य अनुबंध का सामान्य संदर्भ देते हुए अनुबंध करते हैं, तो इस तरह के सामान्य संदर्भ का पक्षकारों के बीच अनुबंध में संदर्भित दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी अन्य अनुबंध से मध्यस्थता खंड को इस अनुबंध में केवल मध्यस्थता खंड के एक विशिष्ट संदर्भ द्वारा शामिल किया जा सकता है (जहां ऐसा संदर्भ दिया जाता है),

(iii) जहां पक्षों के बीच एक अनुबंध में यह प्रावधान है कि उस अनुबंध का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य अनुबंध (जिसमें प्रदर्शन से संबंधित नियम और शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे

का प्रावधान शामिल है) के संदर्भ में होगा, तो, केवल निष्पादन/प्रदर्शन के संबंध में निर्दिष्ट अनुबंध की शर्तें लागू होंगी, न कि अनुबंध में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता के संबंध में, जब तक कि समझौता उपखंड के बारे में कोई विशेष संदर्भ न हो।

(iv) जहाँ अनुबंध यह प्रदान करता है कि एक स्वतंत्र व्यापार या पेशेवर संस्थान के नियमों और शर्तों में मध्यस्थता केलिये किसी भी प्रावधान सहित नियम और शर्तों के प्रारूप को संदर्भ द्वारा शामिल माना जायेगा। कभी -कभी अनुबंध यह भी कह सकता है कि पक्ष उन नियमों और शर्तों से परिचित है या पार्टियों ने उक्त नियम और शर्तों को पढ और समझ लिया है।

(v) जहां पक्षों के बीच अनुबंध यह निर्धारित करता है कि अनुबंध के पक्षों में से किसी एक पक्ष के अनुबंध की शर्तें उनके अनुबंध का एक हिस्सा बनेंगी। (उदाहरण के लिए सरकार के अनुबंध की सामान्य शर्तें जहां सरकार एक पक्ष है) अनुबंध की ऐसी सामान्य शर्तों का हिस्सा बनने वाला मध्यस्थता खंड पक्षों के बीच अनुबंध पर लागू होगा।"

10. अंततः यह पाया गया कि पक्षों का इरादा मुख्य अनुबंध को पूरी तरह से उप-अनुबंध में शामिल करना नहीं था। आगे, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षों के बीच अनुबंध मध्यस्थता खंड लागू नहीं होता था क्योंकि मुख्य अनुबंध लोक निर्माण विभाग, केरल सरकार और ठेकेदार के बीचमें था जिसमें मध्यस्थता खंड के

माध्यम से तीन मध्यस्थों की एक समिति नियुक्त करने का प्रावधान था, जिसमें से केरल राज्य और उसमें प्रत्यर्थी और तीसरा भारत सरकार में सड़क परिवहन सड़क मंत्रालय के महानिदेशक सड़क विकास द्वारा प्रत्येक एक मध्यस्थ नामित किया जाएगा। ठेकदार और उप ठेकेदार के मध्य अनुबंध में केरल राज्य और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थों की समिति की नियुक्ति पूर्ण रूप से अप्रासंगिक थी।

11. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 6 (2), जो इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड तक फैली हुई है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 (5) के समान है और यह निम्नानुसार हैः

"6. मध्यस्थता समझौते की परिभाषा **....**

(2) मध्यस्थता खंड के लिखित रूप या मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक समझौते में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि संदर्भ उस खंड को समझौते का हिस्सा बनाने के लिए है।"

12. इंग्लैंड में निगमन के मुद्दे की व्याख्या को समझना उपयोगी होगा। यह प्रश्न कि क्या निगमन के सामान्य शब्द एक मध्यस्थता समझौते को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं, उच्च न्यायालय, क्वींस बेंच डिवीजन, सी ट्रेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्यूचुअल वॉर रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, द एथेना [2006] ईडब्ल्यूएचसी 2530 (कॉम) में वाणिज्यिक न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न हुआ।।

उक्त मामले में एकल अनुबंध मामले में निगमन और दो अनुबंध मामले के बीच के अंतर को मान्यता दी गई थी। यदि दो पक्षों के बीच एक अनुबंध में एक द्वितीयक दस्तावेज़ का संदर्भ है और वह द्वितीयक दस्तावेज़ एक अनुबंध है जिसके लिए कम से कम एक पक्ष विचाराधीन अनुबंध के पक्षों से अलग है, तो यह दो अनुबंध का मामला होगा। दूसरे शब्दों में, यदि द्वितीयक दस्तावेज़ अन्य पक्षों के बीच है या यदि केवल एक पक्ष है विवाद में अनुबंध पहले के अनुबंध में पक्षकार होता है, जिसके लिए एक संदर्भ दिया जाता है, तो यह दो अनुबंध का मामला होगा और संदर्भ द्वारा इस तरह के एक अनुबंध में सामान्य पूर्व अनुबंध का संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि, यदि संदर्भ एक अनुबंध में मानक शर्तों के लिए है जो 'एकल अनुबंध' का मामला होगा और एक संदर्भ द्वारा मध्यस्थता समझौते को शामिल करने के लिए सामान्य शब्दों के उपयोग की अनुमति है। चूंकि उस मामले में संदर्भ अनुबंध के एक मानक रूप के लिए था जो एक एकल अनुबंध मामला था, न्यायमूर्ति लैंगली ने माना कि निगमन के सामान्य शब्द एक मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त थे।

13. एक पूर्व अनुबंध से बाद के अनुबंध में सामान्य संदर्भ द्वारा मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रश्न फिर से क्वींस बेंच डिवीजन के समक्ष विचार के लिए हबास सिनाई वे टिब्बी गज़लर इस्तिसल एंडस्ट्री ए. एस. बनाम समताल एस. ए. एल. [2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 29 (कॉम) में आया।। उक्त मामले में अनुबंध 10,000 मीट्रिक टन इस्पात कबाड़ की बिक्री से संबंधित था। अनुबंध में सामग्री, मात्रा, मूल्य, शिपमेंट, निर्वहन, दर, भुगतान और अंतिम भार शीर्षक के तहत कई शर्तें थीं। उक्त शर्तों

के अलावा, अनुबंध में एक खंड शामिल था जो निम्नलिखित शर्तों में थाः बाकी सब हमारे पिछले अनुबंधों के समान ही होंगे।

14. उस मामले में जो विवाद उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या ऊपर उल्लिखित सामान्य शब्द मध्यस्थता खंड को शामिल करने में सक्षम थे। उन मामलों के बीच दृष्टिकोण में अंतर जिसमें पक्ष अन्य पक्षों के बीच में शर्तें शामिल करते हैं अथवा, या दोनों में से किसी एक के बीच जहाँ एक ओर तीसरे पक्ष के साथ और दूसरी ओर जिन शब्दों में वे मानक शब्दों को शामिल करते हैं, उन पर ध्यान दिया गया। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों को मान्यता दी गई थी जिनमें पक्षकार एक मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "(1) ए और बी एक अनुबंध करते हैं जिसमें वे मानक शर्तों को शामिल करते हैं। ये एक पक्ष की प्रस्ताव पत्र या आदेश के पीछे, या किसी अन्य दस्तावेज में निहित मानक शर्तें हो सकती हैं जिसके लिए संदर्भ दिया गया है; या ऐसे संगठन के नियमों में सन्निहित शब्द जिनके ए या बी या दोनों सदस्य हैं; या वे किसी विशेष व्यापार या उद्योग में मानक शब्द हो सकते हैं।
>
> (2) ए और बी ए और बी के बीच पहले किसी अन्य अनुबंध या ऐसे अनुबंध में जिसमें वे दोनों पक्ष थे, की शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध करते हैं।

(3) ए और बी ए (या बी) और सी के बीच सहमत शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध करते हैं। सामान्य उदाहरण हैं - एक चार्टर की शर्तों को शामिल करने वाला बिल जिसमें ए एक पक्ष है;

एक अंतर्निहित बीमा की शर्तों को शामिल करने वाले पुनर्बीमा अनुबंध; बीमा की प्राथमिक परत की शर्तों को शामिल करने वाले अतिरिक्त बीमा अनुबंध; और एक मुख्य अनुबंध या उप-उप अनुबंध की शर्तों को शामिल करने वाले निर्माण या इंजीनियरिंग उप अनुबंध जिसमें एक उप अनुबंध की शर्तों को शामिल किया गया है।

(4) ए और बी सी और डी के बीच सहमत शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध करते हैं। लेडिंग, पुनर्बीमा और बीमा अनुबंध और भवन अनुबंध के बिल इस श्रेणी में आ सकते हैं।"

15. हबास के मामले (ऊपर) में, न्यायमूर्ति क्रिस्टोफर क्लार्क ने ' द एथेना' (ऊपर) के मामले में अनुपात का पालन किया और कहा कि एकल अनुबंध मामलों में (श्रेणियां 1 और 2) में, अनुबंध के एक मानक रूप से मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए एक सामान्य संदर्भ पर्याप्त होगा। ऊपर उल्लिखित श्रेणियों 3 और 4 के तहत आने वाले मामलों में, जो दो अनुबंध मामले हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पहले के अनुबंध से मध्यस्थता खंड के एक विशिष्ट संदर्भ पर जोर देकर एक सख्त नियम का पालन किया जाना चाहिए। ऑग्टन बनाम एम. एफ. केंट सर्विसेज मैसर्स आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम मैसर्स थरमोकैबल्स लिमिटेड **[1991] 31**

कॉन एल. आर. **60** में सर जॉन मेगॉ के फैसले पर रखी गई रिलायंस को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया थाः

> "53 मैं निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये खुद को ऑग्टन बनाम केंट और द एथनिकी में अपील न्यायालय के निर्णयों से बाध्य नहीं मानता। दोनों दो-अनुबंध मामले थे। इसके अलावा सर जॉन मेगॉ और लॉर्ड जस्टिस राल्फ गिब्सन के निर्णय कुछ हद तक विरोधाभासी हैं ताकि दो अनुबंध मामलों में भी उनमें से किसी को भी बाध्यकारी प्राधिकरण होने से रोका जा सके। सर जॉन मेगॉ के साथ इवांस एलजे का समझौता "के संबंध में अधिकारियों का विश्लेषण मध्यस्थता खंड और विशेष रूप से चार्टर पार्टी मध्यस्थता खंडों को बिलों में शामिल करना लेडिंग का ओबिटर था।"

16. एक मध्यस्थता खंड की स्वतंत्र प्रकृति से संबंधित बिंदु निगमन से संबंधित विवाद का निर्धारक था जिसका भी उक्त निर्णय में इस प्रकार विचार किया गया हैः

> "51 तथापि, न्यायमूर्ति लैंगली की तरह, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि एकल अनुबंध मामले में, मध्यस्थता खंड की स्वतंत्र प्रकृति को यह निर्धारित करना चाहिए कि इसे शामिल किया जाना है या नहीं। एक वाणिज्यिक वकील शायद समझ सकता है कि एक मध्यस्थता खंड एक अन्य मूल अनुबंध के लिए एक अलग संपार्श्विक अनुबंध है और यह कि "मध्यस्थता खंड" अभिव्यक्ति, उस कारण से,

"मध्यस्थता अनुबंध जो प्राथमिक अनुबंध के लिए सहायक है" के लिए एक गलत नाम है। लेकिन एक व्यापारी को उचित शब्दांकन द्वारा मध्यस्थता खंड (जैसा कि वह इसे कहेंगे) के संबंध में किसी अनुबंध के हिस्से के रूप में और निगमित करने में सक्षम होने के संबंध में और इस तरह के अनुबंध के किसी भी अन्य शब्द के रूप में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये; और यह है, जैसा कि मुझे लगता है कि एक व्यापारी की समझ है कि अदालत द्वारा, प्रभाव देने के लिये निपटारा किया जाना चाहिए। एक व्यापारी जिसने अपने समकक्ष के साथ विभिन्न शीर्षकों के तहत 10 विशिष्ट शर्तों के साथ एक अनुबंध पर सहमति व्यक्त की और उसी समकक्ष के साथ फिर पहले की तरह ही शीर्षकों के तहत समान प्रतिपक्ष शर्तों 1-5 के साथ सहमति व्यक्त की और बाकी के लिए, कि पिछले अनुबंध की सभी शर्तें लागू होनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह जानकर आश्चर्य होगा कि "सभी" की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिएः इसका अर्थ है- मध्यस्थता खंड को छोड़कर सभी।"

17. एकल और दो अनुबंध मामलों की बेहतर समझ के लिए और मानक प्रपत्र शर्तों के संदर्भ में मध्यस्थता पर रसेल 24 वें संस्करण (2015) की जांच करना प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार हैः

"मानक फॉर्म शर्तों, एकल और दो अनुबंध मामलों का संदर्भ। यदि शामिल किये जाने वाला दस्तावेज नियमों और शर्तों का एक मानक स्वरूप निर्धारित है, तो अदालतें यह स्वीकार करने की अधिक सम्भावना रखती हैं कि निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्षों से मध्यस्थता खंड सहित उन मानक शर्तों से अधिक परिचित होने की उम्मीद की जा सकती है। सी ट्रेड मैरीटाईम कोर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्यूचुअल वार रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड ("एथेना") संख्या 2 में न्यायालय ने जिसे "दो अनुबंध मामले" कहा जाता है के रूप में वर्णित जहां मध्यस्थता खंड एक द्वितीयक दस्तावेज में निहित है जो एक अनुबंध है जिसमें कम से कम एक पक्ष विचाराधीन अनुबंध के पक्षों से अलग है, और "एकल अनुबंध मामला" जहां मध्यस्थता खंड मानक शब्दों में दूसरे दस्तावेज़ में पाया जाता है, के बीच अंतर निकाला। फैडरल बल्क कैरीज़ इंक बनाम सी. इतोह एंड कंपनी लिमिटेड (द "फेडरल बल्कर") में बिंघम एल. जे. के कथन पर भरोसा करते हुए, लैंगली जे. ने कहा किः "सिद्धांत रूप में, अंग्रेजी कानून सामान्य शब्दों के उपयोग से मानक शब्दों के समावेश को स्वीकार करता है और, मैं जोड़ूंगा, विशेष रूप से तब जब शब्द आसानी से उपलब्ध हों और यह सवाल एक प्रसिद्ध बाजार में स्थापित खिलाड़ियों के बीच लेनदेन के संदर्भ में उत्पन्न

होता है। सिद्धांत, जैसा कि उक्ति स्पष्ट करती है, जो एक खंड मध्यस्थता है और एक जो अन्य मुद्दों को संबोधित करता है, के बीच अंतर नहीं करता है। इसके विपरीत, और इसी कारण से कि यह अन्य पक्षों से संबंधित है, चार्टर पार्टी/लेडिंग मामलों के बिलों में एक "अधिक सख्त नियम" लागू होता है। इसका कारण यह दिया गया है कि हो सकता है दूसरे पक्ष को प्रासंगिक शर्तों का कोई ज्ञान नहीं हो और न ही ज्ञान का कोई तैयार साधन हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि अधिकारी स्पष्ट करते हैं, एक मध्यस्थता खंड की शर्तों को समायोजन की आवश्यकता हो सकती है यदि उन्हें एक अलग अनुबंध के लिए पक्षों पर लागू किया जाना है।

इसलिए न्यायालय ने मानक रूप की शर्तों और एक अलग अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में निगमन के बीच के अंतर को मजबूत किया और निष्कर्ष निकाला कि: एकल अनुबंध के मामले में निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त हैं, जबकि अपनी प्रकृति से दो अनुबंध मामले में दूसरे अनुबंध के लिए विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, जब तक कि द्वितीयक दस्तावेज़ को मध्यस्थता समझौते वाले मानक फॉर्म शर्तों पर आधारित नहीं कहा जाता है।

उस मामले में, संभवतः विशिष्ट मध्यस्थता खंड के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, इस दृष्टिकोण का बाद के मामलों में समर्थन किया गया है, हालांकि एक अलग अनुबंध, मानक या अन्यथा, की शर्तों को उन समान पार्टियों के मध्य

शामिल करने के बीच थोड़ा अलग लेकिन "भौतिक" अंतर किया गया है - जिन्हें "एकल अनुबंध" मामलों के रूप में माना जाता है, और वह शामिल की जाने वाली शर्तें एक से अधिक पार्टियों के मध्य किये जाने वाले निगमित अनुबंध एक या अधिक अलग-अलग पक्षों के बीच एक अनुबंध में निहित हैं जिन्हें "दो अनुबंध" मामलों के रूप में माना जाता है। (पैरा 2-049)

<u>एकल अनुबंध मामलों का विस्तार</u> हाल ही में, ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने मानक फॉर्म अनुबंधों पर लागू "एकल अनुबंध" सिद्धांत का विस्तार किया है, जहां सामान्य रूप से निगमन के शब्द अन्य प्रकार के अनुबंध के लिए पर्याप्त होंगे, जहां एक ही तर्क लागू होने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार, यदि जिस दस्तावेज़ को शामिल करने की मांग की गई है, वह समान पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, तो अदालतों ने इसे एक "एकल अनुबंध" मामले के रूप में स्वीकार किया है, जहां निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे, भले ही अन्य अनुबंध मानक शर्तों पर नहीं है और एक पूरी तरह से अलग समझौते का गठन करता है। इस दृष्टिकोण के लिए तर्क यह है कि पक्ष पहले से ही उन शर्तों पर अनुबंध कर चुके हैं जिन्हें शामिल किया गया है और इसलिए एक मानक शब्द के समावेश का विरोध करने वाले पक्ष की तुलना में उस शब्द से परिचित होने की अधिक संभावना है जिस पर

भरोसा किया गया है। दूसरे तरीके से कहें, अगर निगमन के सामान्य शब्द बाद वाले के लिए पर्याप्त हैं, तो वे पहले वाले के लिए और भी अधिक पर्याप्त होने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने "एकल अनुबंध" मामले के रूप में भी स्वीकार किया है-एक ऐसी स्थिति जहां निर्दिष्ट अनुबंध मूल अनुबंध के पक्षों में से एक और तीसरे पक्ष के बीच है, जहां समग्र रूप से अनुबंध "एकल वाणिज्यिक संबंध के संदर्भ में किए गए थे।" (पैरा 2-050) [जोर दिया गया]

18. एम.आर. इंजीनियर्स मामले में इस न्यायालय ने, जिस पर पहले विस्तार से चर्चा की गई है, नियम यह यह माना कि पहले के अनुबंध में मध्यस्थता खंड को सामान्य संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जा सकता है। नियम का अपवाद एक व्यापार संघ या एक पेशेवर संस्थान द्वारा अनुबंध के एक मानक रूप का संदर्भ है, जिस स्थिति में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिये एक सामान्य संदर्भ पर्याप्त होगा। इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता 2.3 संस्करण (2007) पर रसेल पर भरोसा किया गया था। एम.आर. इंजीनियर्स मामले में निर्णय के बाद निगमन के सम्बंध में कानून के विकास पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हबास सिनाई वे टिब्बी गज़लर इस्तिसल एंडस्ट्री ए. एस. बनाम समताल एस. ए. एल. [2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 29 (कॉम) में यह माना गया है कि एक पक्ष के एक मानक रूप को भी 'एकल अनुबंध' मामले के रूप में मान्यता दी जाती है। उक्त मामले में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि एकल अनुबंध मामलों में अनुबंध के एक मानक रूप से मध्यस्थता खंड को

शामिल करने के लिए सामान्य संदर्भ पर्याप्त है। एक ओर मान्यता प्राप्त व्यापार संघों व्यावसायिक संस्थानों द्वारा द्वारा मानक रूपों और और दूसरी ओर एक पक्ष की मानक शर्तों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। मध्यस्थता पर रसेल 24 वें संस्करण (2015) भी हबास के मामले पर ध्यान देता है।

19. हमारी राय है कि हालांकि बाद के अनुबंध में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पहले के अनुबंध का सामान्य संदर्भ पर्याप्त नहीं है, लेकिन मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए एक मानक प्रपत्र का सामान्य संदर्भ पर्याप्त होगा। एम. आर. इंजीनियर्स में इस न्यायालय ने व्यापार संघों और व्यावसायिक संस्थानों के अनुबंध के मानक रूप के अपवादों को प्रतिबंधित कर दिया। एम. आर. इंजीनियर्स के मामले में निर्णय के बाद कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए सहमति वाले मानक प्रपत्र का सामान्य संदर्भ पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, एक पक्ष के अनुबंध के मानक रूप का सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। एम. आर. इंजीनियर्स के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले के संस्करण किये गये भरोसे के साथ संयोजन में पढ़ने पर मध्यस्थता पर रसेल 24 वां संस्करण (2015) से गद्यांश का एक अवलोकन निगमन से संबंधित कानून की स्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। हम एम. आर. इंजीनियर के मामले में एक संशोधन के साथ निर्णय से सहमत हैं कि व्यापार संघों और पेशेवर निकायों के साथ एक पक्ष के अनुबंध के मानक रूप का सामान्य संदर्भ मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा।

20. वर्तमान मामले में, खरीद आदेश अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आपूर्ति उसमें उल्लिखित शर्तों और संलग्न मानक नियमों और शर्तों के अनुसार होना चाहिए। प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांकित 15.12.2012 द्वारा डिलीवरी अवधि को छोड़कर खरीद आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि की। माल की डिलीवरी के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों या प्रस्तुतियों से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि खरीद आदेश से जुड़ा मानक प्रपत्र किसी व्यापार संघ या किसी पेशेवर निकाय का है। हालाँकि, उत्तरदाता खरीद आदेश से जुड़े मानक नियमों और शर्तों से अवगत था। क्रय आदेश एक एकल अनुबंध है और मानक प्रपत्र के लिए सामान्य संदर्भ भले ही यह किसी व्यापार संघ या किसी पेशेवर निकाय द्वारा न हो, मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

21. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। न्यायमूर्ति सुशील हरकौली को पक्षकारों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।